

बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर  
द्वितीय तल, पुण्यश्लोका देवी अहिल्या बाई होलकर भवन, शिक्षा संकुल परिसर  
जे.एल.एन मार्ग, जयपुर-302015

क्रमांक : / फर्नीचर / 2025-26 / 165

दिनांक : 04/02/2026

खुली निविदा सूचना संख्या 04/2025-26 दिनांक 05.02.2026

कुल सचिव बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा विनिर्माताओं/अधिकृत विक्रेताओं (OEM/Authorised Dealers) से फर्नीचर (सोफा सेट 3+1+1, सेंटर टेबल, ऑफिसर टेबल, विजिटर्स चेयर, साइड रेक) खुली प्रतियोगी बोली के माध्यम से उपापन हेतु निर्धारित प्रपत्र में मोहरबद्ध एवं सीलबंद एकल निविदा (एक सील बंद लिफाफे में दो सील बंद लिफाफे तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड के पृथक-पृथक) आमंत्रित की जाती है।

विवरण	निर्दिष्ट राशि दिनांक एवं समय
1. अनुमानित लागत	: 3.10 लाख रुपये
2. निविदा जमा कराने की प्रारंभ तिथि एवं समय	: दिनांक 05.02.2026 समय 10:00 AM
3. निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि एवं समय	: दि. 16.02.2026 दोपहर बाद 2:00 बजे तक
4. तकनीकी निविदा खोलने की तिथि एवं समय	: दि. 16.02.2026 को 3:00 PM बजे

क्र.सं.	शुल्क का विवरण	शुल्क	भुगतान का प्रकार	जमा कराने की दिनांक	देय
1	निविदा शुल्क	500/- रुपये	नकद / डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक / ई-चालान (मद 0075-00-800-52-01)	दिनांक 16.02.2026	कुलसचिव बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर
2	बोली प्रतिभूति राशि	अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत राशि रुपये 6,200/-	नकद/डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/ई-चालान (मद 8443-00-103-00-00)	दोपहर बाद 02:00 तक	कुलसचिव बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर

निविदा शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि नकद/डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/ ई-चालान कुलसचिव बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर कार्यालय में दिनांक 16.02.2026 समय दोपहर बाद 02:00 बजे तक निविदा प्रपत्र के साथ ऑफलाईन जमा कराने होंगे जिस पर निविदा के कार्य का नाम -निविदादाता का नाम, डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/ई-चालान/नकद इत्यादि स्पष्ट अंकित करें। जिन निविदादाताओं के उपरोक्त वांछित राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/ ई-चालान/नकद निर्दिष्ट समय तक प्राप्त नहीं होंगे, उन -निविदादाताओं की तकनीकी बिड नहीं खोली जावेगी। तकनीकी बिड में सफल घोषित निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।

निविदा प्रपत्र, नियम व शर्तों से संबंधित पूर्ण विवरण का अवलोकन राज्य लोक उपापन पोर्टल <http://sppp.raj.nic.in> एवं [amtedivyanguniversity.ac.in](http://amtedivyanguniversity.ac.in) पर किया जा सकता है।

निविदा को बिना किसी सूचना एवं कारण बताये निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार कुलसचिव बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर के पास सुरक्षित रहेगा।

  
कुलसचिव

बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर  
द्वितीय तल, पुण्यश्लोका देवी अहिल्या बाई होलकर भवन, शिक्षा संकुल परिसर  
जे.एल.एन मार्ग, जयपुर-302015  
निविदा की शर्तें

- निविदादाताओं द्वारा निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मोहरबद्ध एवं सीलबंद एकल निविदा (एक सील बंद लिफाफे में दो सील बंद लिफाफे तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड के पृथक-पृथक) ऑफ-लाईन प्रस्तुत की जानी होगी। तकनीकी रूप से सफल बिडर की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी। तकनीकी रूप से अस्वीकृत बिड पर विचार नहीं किया जावेगा।
- दरें एफ. ओ. आर. अर्थात गन्तव्य स्थान बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, पुण्यश्लोका देवी अहिल्या बाई होलकर भवन द्वितीय तल, जयपुर तक केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा देय समस्त करों यथा जी. एस. टी. या अन्य कोई कर तथा परिवहन व्यय, लोडिंग अनलोडिंग, इंस्टालेशन चार्ज सहित देनी होगी। अन्य कोई राशि कार्यालय द्वारा पृथक से देय नहीं होगी।
- कोई भी डीलर यदि जी.एस.टी. अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है तो वह निविदा नहीं देगा। इनके अभाव में बोलियों पर विचार नहीं किया जायेगा। जी.एस.टी. देयता प्रमाण-पत्र की छायाप्रति प्रपत्र जीएसटीआर-3बी में संलग्न की गई हो। (केवल 30 सितम्बर, 2025 की)
- निविदा इस कार्यालय में ऑफ-लाईन प्रस्तुत करनी होगी।
- विहित समय एवं तारीख के पश्चात् जो भी बोलियां प्राप्त होंगी उन्हें किसी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- बोली प्रतिभूति राशि :-**  
(क) तकनीकी बिड के सीलबंद लिफाफे में राशि रु. 6,200- की बोली प्रतिभूति राशि प्रस्तुत करनी होगी। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। यह राशि कुलसचिव बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/ई-चालान/नकद में से किसी रूप में जमा करायी जा सकती है। राजस्थान में पंजीकृत MSME द्वारा बोली प्रतिभूति राशि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अनुसार जमा करवाई जा सकती है। इस हेतु MSME प्रमाण-पत्र आवश्यक रूप से संलग्न करना होगा। बोली प्रतिभूति राशि में छूट/कम राशि जमा कराने के संबंध में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 42 के प्रावधान लागू होंगे। बोली प्रतिभूति राशि में छूट/कम राशि जमा कराने के संबंध में आवश्यक प्रमाण-पत्र संलग्न करने होंगे।  
(ख) असफल निविदादाताओं की बोली प्रतिभूति राशि सफल निविदा को अंतिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथासंभव शीघ्र लौटा दी जावेगी।  
(ग) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रद्द की गई या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर के पास जमा प्रतिभूति राशि को नवीन निविदा के लिए बोली प्रतिभूति राशि के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगा।  
(घ) बोली प्रतिभूति राशि हेतु चालान मद 8443-00-103-00-00 में बनाया जावेगा।
- बोली प्रतिभूति राशि का समपहरण:-** बोली प्रतिभूति राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहरण कर लिया जायेगा:-  
(क) जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।  
(ख) जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित करार को निष्पादित नहीं करता है।  
(ग) जब निविदादाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद कार्य संपादन प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता हो।  
(घ) जब वह निर्धारित समय के अन्तर्गत आदेशों के अनुसार सामग्री आपूर्ति करने में असफल रहता है अथवा संतोषजनक सेवाएं देने में असमर्थ रहता है।
- वित्तीय-बिड मूल्यांकन का तरीका:-**  
तकनीकी रूप से योग्य निविदादाताओं की वित्तीय बिड को निर्धारित दिनांक को निर्धारित समय पर उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जाएगा तथा न्यूनतम दरदाता की दर को एल-वन माना जावेगा। यदि एक से अधिक निविदादाता एल-वन हो तो जिस निविदादाता का गत तीन वित्तीय वर्षों का टर्नओवर अधिक होगा, को एल-वन माना जावेगा। टर्नओवर हेतु सनदी लेखाकार (चाटर्ड अकाउंटेंट) का प्रमाण-पत्र मान्य होगा। प्रमाण-पत्र पर यूडीआईएन नम्बर अंकित होना आवश्यक है। इसके अभाव में प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- यदि न्यूनतम दर दाता जिसकी दरों को उपापन संस्था द्वारा स्वीकृत किया गया है, के द्वारा क्रय आदेश के अनुसार पूर्ण आपूर्ति नहीं कि जा सकती हो तो न्यूनतम दाता की स्वीकृत दर पर द्वितीय न्यूनतम दर दाता से भी सामग्री क्रय करने के लिए उपापन संस्था स्वतंत्र होगी।
- यदि निविदादाता ऐसी कोई शर्त आरोपित करता है जो उसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है तो उसकी निविदा को रद्द कर दिया जावेगा। अर्थात सशर्त बोली स्वीकार योग्य नहीं होगी।
- (अ) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर को लिखित में निविदादाता द्वारा दी जावेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जावेगा।  
(ब) संविदा के सम्बन्ध में फर्म के किसी भी नये भागीदार/भागीदारों का निविदादाता द्वारा फर्म से सम्बन्ध स्वीकार नहीं किया जावेगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं कार्यालय को इस सम्बन्ध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते प्राप्ति स्वीकृति के लिए निविदादाता की रसीद को बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गई किसी भागीदार की रसीद उन सब को बाध्य करेगी। निविदादाता अपनी संविदा या उसके किसी भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौंपेगा या उपभाड़े पर नहीं देगा।

12. करार एवं कार्य संपादन प्रतिभूति निक्षेप :-।

(क) सफल निविदादाता को स्वीकृत पत्र की दिनांक से 7 दिन की अवधि के भीतर रूपये 500/- मूल्य के नॉन ज्यूडिशियन स्टॉम्प पेपर पर (जिसका व्यय स्वयं निविदादाता द्वारा वहन किया जावेगा) एक करार-पत्र सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-द्वितीय के एस. आर. प्ररूप 17 में निष्पादित करना होगा तथा प्रावधित मूल्य, जिसके लिए निविदा स्वीकार की गई है, उसके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर कार्य संपादन प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति निविदा को स्वीकार किये जाने की सूचना प्रेषित किये जाने की दिनांक से सात दिन में जमा कराई जायेगी। कार्य संपादन प्रतिभूति राशि जमा कराने के संबंध में छूट/कम राशि जमा कराने के क्रम में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2013 के नियम 75 के प्रावधान लागू होंगे। तथा कार्य संपादन प्रतिभूति राशि जमा कराने के संबंध में छूट/कम राशि जमा कराने के संबंध में आवश्यक प्रमाण-पत्र संलग्न करने होंगे।

(ख) निविदा के समय जमा कराई गई बोली प्रतिभूति राशि को कार्य संपादन प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जा सकेगा।

(ग) बोली प्रतिभूति/कार्य संपादन प्रतिभूति राशि पर कार्यालय द्वारा कोई ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।

(घ) कार्य संपादन प्रतिभूति राशि के रूप में नकद राशि/शिड्यूल बैंक का ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/ई-चालान मान्य होंगे।

13. कार्य संपादन प्रतिभूति राशि का समपहरण :- प्रतिभूति की राशि को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहरण (forfeit) किया जायेगा:-

(क) जब संविदा की किसी शर्त/अथवा शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

(ख) जब निविदादाता सम्पूर्ण सामग्री की आपूर्ति संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहरण करने के मामले में युक्तियुक्त नोटिस दिया जावेगा इस सम्बन्ध में कार्यालय के अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(घ) सामान आपूर्ति में असफल रहने पर बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने पर उसमें जो भी व्यय होगा निविदादाता से उसकी प्रतिभूति राशि में से अथवा उसको देय बिल की राशि के भुगतान में से कटौती की जायेगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर.एक्ट या प्रवृत्त अन्य किसी कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

14. बोली की वैधता अवधि 90 दिवस की होगी।

15. जिस बोलीदाता की बोली दर स्वीकृत की जाएगी उसे क्रय आदेश की दिनांक से दस दिवस में सामान की आपूर्ति करनी होगी। प्रदाय की गई सभी वस्तुएं निविदा में निर्धारित की गई विशिष्टताएं (specification) (ऐनेक्सर-ग) के अनुरूप होंगी।

16. निरीक्षण एवं परीक्षण :- प्रदाय जब भी प्राप्त किया जायेगा उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जायेगा कि वे विनिर्देशों के अनुरूप हैं।

17. कार्यालय इसमें से किन्हीं वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में सामान खरीदता है तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

18. सफल निविदादाता को क्रय आदेश के अनुसार सामग्री का प्रदाय करना होगा, तथा उचित पैकिंग करेगा ताकि परिवहन के दौरान नुकसान नहीं हो। परिवहन के दौरान किसी प्रकार की टूट-फूट, नुकसान, हानि या किसी प्रकार की कमी होने के मामले में, निविदादाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रियों की जांच/निरीक्षण किये जाने पर पायी गई ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा। इसके लिए अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा। अस्वीकृत/अमान्य (रिजेक्टेड) सामान को अविलम्ब कार्यालय से ले जाना होगा, जिसके लिए कोई भुगतान इस कार्यालय द्वारा नहीं किया जावेगा।

19. गारन्टी/वारंटी :-निविदादाता द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री पर 36 माह की अवधि तक onsite warranty प्रदान की जानी होगी, जिसका प्रमाण सामग्री के साथ ही उपलब्ध कराया जाना होगा तथा इस तथ्य के बावजूद कि क्रेता ने सुपुर्द सामग्री को अनुमोदित कर दिया है, यदि निर्दिष्ट गारन्टी/वारन्टी अवधि में आपूर्ति सामग्री गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पायी गयी तो क्रेता अधिकारी ऐसी सम्पूर्ण/आंशिक सामग्री को रद्द करने का हकदार होगा। ऐसी रद्द की गयी सामग्री विक्रेता की जोखिम पर होगी तथा, माल आदि को रद्द करने से संबंधित समस्त उपबन्ध लागू होंगे। निविदादाता को, यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा जाए, तो वह उस माल को या उसके किसी भाग को, जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है, बदलना होगा अन्यथा निविदादाता ऐसे नुकसान के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गयी शर्त के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होगी।

20. परिसमापित नुकसान :-

(1) परिसमापित नुकसान के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनका निविदादाता प्रदाय करने में असफल रहा है:-

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5%

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए 5%

(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक के लिए 7.5%

(घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक विलम्ब के लिए 10%

(2) प्रदाय में विलम्ब अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जाएगा।

(3) परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10% होगी।

(4) यदि प्रदायकर्ता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिए समय में वृद्धि कराना चाहता है, तो वह लिखित में कार्यालय को आवेदन करेगा। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

(5) यदि माल प्रदाय करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसान रहित की जा सकेगी।

21. वसूली :-परिसमापित नुकसानी, कम प्रदाय, टूट-फूट, रद्द की गई वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। प्रदायकर्ता कम प्रदाय, टूट-फूट, रद्द किए गए सामान की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायकर्ता संतोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली उसे देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप

से की जाएगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी. डी. आर. एक्ट या प्रवृत्त अन्य कानून के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।

22. **भुगतान :-**

- (क) निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जायेगा। सभी प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किये जायेंगे। किसी भी परिस्थिति में अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।
- (ख) विवादास्पद मदों में राशि का 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक को रोका जायेगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जायेगा।
- (ग) उन मामलों में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जायेगा जब उनका परीक्षण कर लिया जाये तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित निर्देशों के अनुरूप हों।
23. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :-
- (i) यदि भागीदारी फर्म हो तो "पार्टनरशिप डीड" की अनुप्रमाणित प्रति।
- (ii) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।
- (iii) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।
- (iv) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र।
24. संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के सम्बन्ध में या अन्य किसी भी प्रकार का विवाद होने पर कार्यालय का निर्णय अन्तिम होगा।
25. समस्त विधिक कार्यवाहियां यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो जयपुर स्थित न्यायालय में ही की जाएगी। अन्यत्र नहीं की जाएगी।
26. निविदा दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता द्वारा हस्ताक्षर करने होंगे।
27. बोली दस्तावेज एवं निबंधन एवं शर्तों के निर्वचन के संबंध में किसी प्रकार की कठिनाई/समस्या होने पर कुलसचिव बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर से संपर्क किया जा सकता है।
28. अन्य शर्तें सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेश, परिपत्र एवं अधिसूचनाओं के अनुसार लागू होंगी।
29. मैं/हम बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा जारी की गई इस निविदा में वर्णित सभी शर्तों से तथा उक्त निविदा की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। सभी पृष्ठों पर इसमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं। हम राज्य सरकार के उपापन संबंधी अधिनियम/नियम आदेश से आबद्ध होना स्वीकार करते हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर  
(मय नाम पता एवं मोहर)



## तकनीकी-बिड

(पृथक लिफाफे में सीलबंद करके दें)

विषय:- फर्नीचर (सोफा सेट 3+1+1, सेंटर टेबल, ऑफिसर टेबल, विजिटर्स चेयर, साइड रेक ) के उपापन हेतु निविदा-प्रपत्र

1. निविदादाता का नाम एवं डाक का पता:-.....
2. निविदादाता फर्म/संवेदक का फोन एवं मोबाईल नम्बर.....
3. निविदादाता का ई-मेल एड्रेस:-.....
4. निविदादाता के बैंक का नाम..... आई.एफ.एस.सी. .... एवं खाता संख्या.....
5. सन्दर्भ निविदा सूचना क्रमांक:- 04/2025-26 दिनांक:- 05.02.2026
6. निविदा शुल्क की नगद जमा राशि..... रसीद संख्या..... दिनांक...../बैंक का नाम.....  
..... बैंकर्स चैक या ड्राफ्ट संख्या..... दिनांक.....ई-चालान संख्या.....दिनांक.....  
संलग्न है।
7. बोली प्रतिभूति राशि, नकद जमा राशि.....रसीद संख्या.....दिनांक..... बैंक का नाम....., बैंकर्स  
चैक या ड्राफ्ट संख्या..... दिनांक..... ई-चालान संख्या.....दिनांक.....संलग्न है।
8. पंजीकरण से सम्बन्धित सूचना :- निविदादाता द्वारा निम्नलिखित पंजीकरण विवरण निर्धारित कॉलम में प्रस्तुत किया  
जावेगा तथा प्रमाण-पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति संलग्न करनी होगी। किसी अधिनियम में पंजीकरण नियमानुसार  
आवश्यक नहीं है, तो इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

क्र.सं.	विवरण	रजि.सं	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	वस्तु एवं सेवाकर (GST)				
2	आयकर (पैन नम्बर)				
3	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

9. राजस्थान में पंजीकृत MSME द्वारा बोली प्रतिभूति राशि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं  
राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अनुसार जमा करवाई जा सकती है। इस हेतु MSME प्रमाण-पत्र  
आवश्यक रूप से संलग्न करना होगा।
10. निविदादाता द्वारा जीएसटी देयता प्रमाण-पत्र की छायाप्रति प्रपत्र जीएसटीआर-3बी में संलग्न की जानी होगी। (केवल  
30 सितम्बर, 2025 की)
11. निविदादाता द्वारा विनिर्माता/अधिकृत विक्रेता के प्रमाण-पत्र/ अधिकृत पत्र की छायाप्रति अनुलग्नक 'क' के साथ  
संलग्न की जानी होगी।
12. निविदादाता का गत तीन वित्तीय वर्षों (2022-23 से 2024-25 तक) का उत्पाद/विक्रय सामग्री का प्रतिवर्ष टर्नओवर  
राशि रु. 3.10 लाख होना चाहिये। इस बाबत सीए का यू.डी.आई.एन. अंकित प्रमाण पत्र संलग्न करें।
13. मैं/हम बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर, द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या 04/2025-26 दिनांक  
05.02.2026 में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को मेरे/हमारे द्वारा  
स्वीकार किये जाने प्रमाण मे मैंने/हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं) में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से  
बाध्य होना स्वीकार करते हैं। स्वीकार किये जाने के प्रमाण स्वरूप मैंने/हमने सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।
14. घोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप अनुलग्नक "ख" संलग्न है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर  
नाम मय सील

नाम \_\_\_\_\_  
पूरा पता \_\_\_\_\_  
मो.नं. \_\_\_\_\_  
ई.मेल. \_\_\_\_\_

## वित्तीय-बिड प्रपत्र

(पृथक लिफाफे में सीलबंद करके दें)

कुलसचिव बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर,, राजस्थान के कार्यालय में फर्नीचर (सोफा सेट 3+1+1, सेंटर टेबल, ऑफिसर टेबल, विजिटर्स चेयर, साइड रेक ) के उपापन हेतु खुली निविदा से सम्बन्धित सभी शर्तों को मैंने/हमने पढ़ ली है और ये शर्त मुझे/हमें स्वीकार्य है तथा कुलसचिव बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर, राजस्थान के कार्यालय में उक्त सेवाओं के उपापन के लिए खुली निविदा में वित्तीय बोली की दरें निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत हैं:-

क्र.सं	नाम सामग्री	सामग्री की मात्रा	कुल राशि (जी.एस.टी, अन्य कर एवं अन्य व्ययों सहित)
1	सोफा सेट (3+1+1)	3	
2	विजिटर्स चेयर	9	
3	सेन्टर टेबल	3	
4	ऑफिसर टेबल	3	
5	साइड रेक	3	

नोट:-

1. दरें एफ. ओ. आर. अर्थात गन्तव्य स्थान बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, पुण्यश्लोका देवी अहिल्या बाई होलकर भवन द्वितीय तल, जयपुर तक केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा देय समस्त करों यथा जी. एस. टी. या अन्य कोई कर तथा परिवहन व्यय, लोडिंग अनलोडिंग, इंस्टालेशन चार्ज सहित देनी होगी। अन्य कोई राशि कार्यालय द्वारा पृथक से देय नहीं होगी।
2. न्यूनतम दर के आधार पर ही सफल निविदादाता (L1) का चयन किया जावेगा।
3. एक से अधिक न्यूनतम दर दाताओं की समान दर प्राप्त होने पर गत तीन वित्तीय वर्षों (2022-23, 2023-24 एवं 2024-25) का सर्वाधिक टर्नओवर वाले निविदादाता को कार्य संपादनार्थ सफल निविदादाता (L1) के रूप में चयनित किया जावेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर  
नाम मय सील

नाम \_\_\_\_\_  
पूरा पता \_\_\_\_\_  
मो.नं. \_\_\_\_\_  
ई.मेल. \_\_\_\_\_

निविदादाताओं द्वारा घोषणा जो तकनीकी बिड के साथ प्रस्तुत की जानी है

मैं/हम/घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन सामान के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाईड विनिर्माता/प्राधिकृत डीलर हैं। निविदा सूचना में मेरे/हमारे द्वारा दी गयी समस्त सूचना एवं दस्तावेज सही है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो हमारे विरुद्ध सभी विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकेगी। हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहरत कर लिया जाएगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाएगा एवं हमें राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम, 2013 के अन्तर्गत अनर्हकारी (अयोग्य) माना जा सकेगा।

संलग्न:- प्राधिकार प्रमाण-पत्र



निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

निविदादाता का नाम-----

पूर्ण पता-----  
-----

टेलिफोन नं. (निवास)-----

(कार्यालय)-----

फैक्स/ई-मेल-----

## घोषणा-पत्र

खुली निविदा की समस्त जानकारी/शर्तों का मैंने/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मुझे/हमें यह भी स्वीकार है कि कुलसचिव बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान का निर्णय हमारे लिये मान्य होगा। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मेरी/हमारी फर्म वस्तु एवं सेवा कर (GST), आय कर (पैन नम्बर) एवं राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत है, जिसके प्रमाण-पत्रों की प्रतियाँ कार्यालय को निविदा के साथ उपलब्ध कराई जा रही हैं और यदि हमारी फर्म का उक्त नियमों के अन्तर्गत वर्तमान में जिस अधिनियम में पंजीकरण आवश्यक नहीं है उसका तदनुसार वचन पत्र (Undertaking) निविदा के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है।

फर्म द्वारा वास्तव में निविदा प्रपत्र में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित मशीन/उपकरण/तकनीकी अनुभव व तकनीकी कर्मचारी आदि उपलब्ध है। केन्द्र/राज्य सरकार/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वायत्तशासी संस्थान/निगम/बैंक तथा इस उपापन संस्था द्वारा मेरी/हमारी फर्म को राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 46 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 39 के अनुसार अपात्रता के लिए विवर्जित (Debarred) नहीं किया गया है। मेरी/हमारी फर्म/प्रतिष्ठान के विरुद्ध केंद्र सरकार, राज्य सरकार/स्वायत्तशासी संस्था के कार्यालयों द्वारा ब्लैक लिस्ट की कार्यवाही नहीं की गई है ना ही कोई कार्यवाही विचाराधीन है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी बोली प्रतिभूति/एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहृत किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

दिनांक :-

स्थान :-



निविदादाता के हस्ताक्षर मय रबर सील

निविदादाता का नाम :-.....

पूर्ण पता :-.....

## उपापन किये जाने वाले सामान के तकनीकी स्पेसिफिकेशन

Sr. N	Name of item	Specifications
1	Sofa set (3+1+1)	Supply of sofa set (3 pieces) consisting of one 3-seater and two single seaters (1+1) Frame made of solid Sagwan wood in single-piece construction. Upholstered with approved tapestry cloth (₹550/meter) and Provided with nylon belt support. 3-seater seating length 68 inches (excluding arms). Seat with 4" thick HR foam ( 40 density) and back with 32 density foam.
2	Visitor Chair	Supply of fix type visitors chair, chair base/frame made of 1" round steel, seat and back made of 12mm hot pressed fiber supports unholstered with foam of 32 density, covered with clothe tepstry of approved colour on seat and back. Chair shall have 'D' shape PU handle attached with the seat and back.
3	Center Table	Lenth 48 inch X wide 24 inch X height 18 inch and top thickness 1.5 inch. The frame should be made out of sagwan wood with Full polished.
4	Officer Table	Lenth 84 inch X wide 42 inch X height 30 inch. table top thickness 1.5 inch. The frame is made By Prelamboard with one side three drawer and other side one box (Two parts inside the box) with lock
5	side rack	Side rack size length 36 inch X wide 24 inch X height 30 inch made of pre laminated particle board ( Two part inside the box ) with lock .

mt

**Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest**

Any person participating in a procurement process shall-

- (a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) Not indulge in any collusion, bid rigging or anticompetitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) Not misuse any information shared between the procuring entity and the bidders with intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) Disclose conflict of interest, if any; and
- (h) Disclose any previous transgressions with any entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

**Conflict of interest. -**

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest. A Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

(i) A bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more parties in the bidding process if, including but not limited to:

- (a) Have controlling partners/shareholders in common; or
- (b) Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- (c) Have the same legal representative for purposes of the bid; or
- (d) have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the bid of another bidder, or influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process; or
- (e) The bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one bid will result in the disqualification of all bids in which the bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a bidder, in more than one bid; or
- (f) the bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the goods, Work/supply's or services that are the subject of the Bid; or
- (g) Bidder or any of its affiliates has been hired (or proposed to be hired) by the procuring entity as engineer-in-charge/consultant for the contract

*Mh*

**Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications**  
**Declaration by the Bidder**

In relation to my/our Bid submitted to Registrar Baba Amte Divyang University, Jaipur for procurement of furniture (sofa set 3+1+1, Center table, Officer table, visitor chair, Side rack) in response to their Notice Inviting Bid No. 04 dated 05.02.2026, I/we ..... hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entry;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the union and the state government or any local authority as specified in the Bidding Document.
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :

Place:



Signature of bidder

Name : -----

Designation:-----

Address:-----

### Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is **Vice-chancellor** Baba Amte Divyang University , Jaipur  
The designation and address of the Second Appellate Authority is commissioner cum Special **Secretary. Department of Special Disabled, Rajasthan Jaipur.**

**(1) Filing an appeal:-** if any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring entity is in contravention to the provisions of the Act or the rules or the guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate authority, as specified in the Bidding document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved: Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a bidder who has participated in procurement proceedings: Provided further that in case a procuring entity evaluates the technical bids before the opening of the financial bids, an appeal related to the matter of financial bids may be filed only by a bidder whose technical bid is found to be acceptable.

**(2)** The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavor to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

**(3)** If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the order passed by the first appellate authority, the bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be, may file a second appeal to second appellate authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the first appellate authority, as the case may be.

**(4) Appeals not to lie in certain cases: -** No appeal shall lie against any decision of the procuring entity relating to the following matters, namely:-

- (a) Determination of need of procurement
- (b) Provisions limiting participation of bidders in the bid process
- (c) The decision of whether or not to enter into negotiations
- (d) Cancellation of a procurement process
- (e) Applicability of the provisions of confidentiality

**(5) Form of Appeals: -**

- (a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to first appellate authority or second appellate authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

**(6) Fee for filing Appeal: -**

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be nonrefundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a scheduled bank in India payable in the name of appellate authority concerned.

**(7) Procedure for disposal of Appeal: -**

- (a) The first appellate authority or second appellate authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the first appellate authority or second appellate authority, as the case may be shall- (i) hear all the parties to appeal present before him; and (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the appellate authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the state public procurement portal.

*Mh*

## **Annexure D : Additional Conditions of Contract**

### **1. Correction of arithmetical errors**

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis: i.e. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

### **2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities**

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, Work/supply or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

### **3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)**

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

SCHEDULE 'H': CONDITION OF CONTRACT

FORM No. 1

[See rule 83]

**Memorandum of Appeal under the Rajasthan  
Transparency in Public procurement Act, 2012**

Appeal No.....of .....Before the.....  
.....(First/Second Appellate authority)

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:

(ii) Official address, if any:

(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

(i)

(ii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the office/authority that passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant propose to be represented by a representative the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal: ..... (Supported by an affidavit)

7. Prayer:.....

Place:.....

Date: .....

**Appellant's Signature**

